Committee stated inter alia in its report that it could not come to any conclusion as to whether there was actually any problem due to radioactivity or not, for want of examination of the issues by specialists in effects of radioactivity. In its report, this Committee recommended inter alia that a detailed survey be carried out by the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) in respect of the effects of the uranium mines at Jaduguda in the surrounding areas. Accordingly, a team consisting of radiation experts of the Health Physics Unit of the BARC at Jaduguda and medical officers of the State Government as well as UCIL Hospital carried out a door-to-door survey of 17 villages around Jaduguda and examined about 4000 persons. This initial survey was followed by detailed pathological and other tests of selected persons at the UCIL Hospital and Tata Main Hospital, Jamshedpur. This team finally shortlisted 29 cases and felt that further examination by Radiation Experts of BARC was required to assess if these cases could be attributed to effects of radiation. An expert team of Medical Officers and Health Physicists of BARC visited Jaduguda and alongwith Doctors of the State Government, UCIL Hospital and Tata Main Hospital re-examined the shortlisted cases. As per the findings of this team of Experts, the disease pattern cannot be ascribed to radiation exposure in any of these cases.

कृषि ऋण हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य

2636. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 व 1998-99 में किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया था और किसानों को वस्तुत: कितना कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया; और

(ख) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितना कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है और पंचवर्षीय योजनावधि के शेष वर्षों में राजस्थान के किसानों को कुल कितना कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कृषि ऋण तथा सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल द्वारा नौवीं योजनावधि के लिए लगाए गए अनुमान के अनुसार किसानों को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित कुल कृषि ऋण लगभग 229750 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान किसानों को प्रदान किए गए ऋण और उनके लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लक्ष्य	प्रदान किए गए ऋण
1997-98	33,375	31,696.41 (अनंतिम)
1998-99	38,645	38,054.70 (अनुमानित)

ऋण मुहैया कराने के लिए राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है। नाबार्ड ने राजस्थान के लिए वर्ष 1997-98 से 2001-2002 (नौवीं योजना अवधि) तक की अवधि के लिए क्षमता से जुड़ी योजना पर आधारित कृषि ऋण की अनुमानित आवश्यकता 13,862.40 करोड़ रुपये आंकी है।

कृषि में विविध खेती

2637. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेती की विविधता दिनों-दिन नष्ट होती जा रही है और चावल व गेहूं की कई किस्में लुप्त होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो लुप्त हुई किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित "बारहा नाजा" परम्परा को हतोत्साहित किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी हां, यह सही है कि भारतीय कृषि में विविधता धीरे-धीरे घट रही है, क्योंकि चावल और गेहूं की विभिन्न देशी किस्मों/स्थानीयों प्रजातियों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया जा रहा है।

(ख) चावल और गेहूं की अनेक स्थानीय प्रजातियां/परम्परागत किस्में या तो विलुप्त हो गयी है या विलुप्त होने के कगार पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगायी जाने वाली बिन्दली और तिलकचन्दन जैसी चाँवल की कुछ स्थानीय प्रजातियों/किस्मों को अधिक उपज देने वाली किस्मों द्वारा बदला जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा और पंजाब में उगायी जाने वाली झोना-349और पलमल किस्मों के स्थान पर नई अधिक उपज देने वाली किस्मों को उगाया जा रहा है। चावल की स्थानीय किस्में नामतः रिब्बा, झालु, लालमति, झुमकाया, काप्लेमा, थापाचीनी, नागमति, साठा, बादशाहभोग तथा गेहूं की मिश्री मुन्डेरियां और कन्कू जैसी कुछ स्थानीय किस्में पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) यह सत्य नहीं है कि "बारहा नॉजा" परम्परा, जो कि गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, को निरुत्साहित किया जा रहा है बल्कि यह परम्परा धीरे-धीरे अपने आप कम हो रही है। इसके लिए कुछ कारण नीचे दिये गए हैं:—

(i) किसान नई किस्मों के फायदों और अधिक उपज को देखते हुए "बारहा नॉजा" परम्परा को धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं।

(ii) नगदी फसलों को वरीयता देना।

(iii) स्थानीय किस्मों की उपयोगिता के प्रति किसानों की अनभिज्ञता।

SmalL Farmers Agri-Business Consortium

2638. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any tangible progress in implementation of the Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC);

(b) what is the extent of the activity, State-wise of SFAC;

(c) the number of such Centres in Andhra Pradesh;

(d) whether Government propose to improve such SFAC in Andhra Pradesh in 1999-2000; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (e) (1) Following projects are at the appraisal stage for implementation by the Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC):

(i) Integrated Coconut Development/ Acquaculture/Floriculture	Ernakulum (Kerala)
(ii) Horticulture (Mango grafting, Papaya, Organic Vegetables and Floriculture)	Dharmapuri (Tamil Nadu)
(iii) Horticulture Oilseeds and Poultry	Pondicherry (U.T.)
(iv) Arid-horticulture Seed Multiplication (Groundnut) and procesing of Non-traditional Oils	Bikaner (Rajasthan)
(v) Horticulture (Mango, Chicko) and Acquaculture	Valsad (Gujarat)
(vi) Vegetables and Flower Marketing and Wasteland Development	Midnapur (West Bengal)
(vii) Sustainable Intensive Farming and Creation of Infrastructure	Barpeta (Assam)
(viii) Horticulture (Fruits Nurseries) Kewada, Aromatic Plants and Vegetable Seed production Inland and Coastal Acquaculture	Gajapati (Orissa)
(ix) Cotton Ginning Pressing, Chilly, Oleoresin Extraction and Particle Board Making	Dharwad (Karnataka)
(x) Horticulture (Fruit Flowers and Vegetables) Mustard Seed Production Sericulture, Sheep and Dairy Farming, Wasteland Development	Mehboob Nagar (Andhra Pradesh)